

अंबाजोगाई कृषि तंत्र विद्यालय के वस्तिगृह के लिए ३० करोड़ का फंड मंजूर

आ. नमिता मुंदडा के प्रयासों को सफलता

अंबाजोगाई, १ मार्च (प्रतिनिधि) - अंबाजोगाई स्थित कृषि तंत्र विद्यालय के विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए नए वस्तिगृह (छात्रावास) भवनों के निर्माण हेतु ३० करोड़ रुपये के फंड को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसमें से २ करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की भी सरकार ने मंजूरी दी है। यह फंड महाराष्ट्र सरकार के वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यालय के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। केज विधानसभा क्षेत्र की विधायक नमिता मुंदडा ने इस फंड की मंजूरी के लिए लगातार प्रयास किया था। उनके सतत प्रयासों और शासन स्तर पर की गई मांग के बाद सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधा आ. नमिता मुंदडा लंबे समय से कृषि तंत्र विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक और सुक्षित वस्तिगृह की मांग कर रही थीं। इसके लिए उन्होंने शासन स्तर पर कई पत्र व्यवहार औलगातार फॉलो-अप किया। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए अलग-अलग १४.८७ करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई। सरकार ने प्रत्येक वस्तिगृह के

लिए १-१ करोड़ रुपये (कुल २ करोड़ रुपये) की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति २७ फरवरी को दी है। इस निर्णय से अंबाजोगाई में विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रस्ताव हुआ है। शासन की कृषि शिक्षा पर विशेष नजर अंबाजोगाई में

कृषि क्षेत्र के विकास, तकनीकी सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। कृषि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने पूँजीगत निधि (कैपिटल फंड) को मंजूरी दी है और उन्होंने कृषि शिक्षा के स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।

विधायक नमिता मुंदडा ने किया सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार के इस फैसले से अंबाजोगाई कृषि तंत्र विद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में कृषि शिक्षा के विकास को नई दिशा मिलेगी।

आरटीई के तहत गरीब छात्रों के प्रवेश पर धनाढ़ीयों का कब्जा, फर्जी दस्तावेजों से कराया एडमिशन

मनोज जाधवने जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की शिकायत

बीड़, १ मार्च (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र में शिक्षा के अधिकारी (ठड़) कानून के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया चलाई जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में वास्तविक जरूरतमंद छात्रों को वंचित रखा जा रहा है, जबकि धनाढ़ीय लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए रीटें हड्डप रहे हैं।

शहर की पोदार इंग्लिश स्कूल, गुरुकुल इंग्लिश स्कूल और संत ज्ञानेश्वर इंग्लिश स्कूल में प्रवेश पाने के लिए अधिकारीयों ने अपडेट किए गए आधार कार्ड, फर्जी किरायानामा और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है।

शिकायत और जांच की मांग आरटीई कार्यकर्ता एवं शिवसंग्राम युवा नेता मनोज जाधव ने

जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी से इस मामले की जांच करने और फर्जी प्रवेश को रद्द करने की मांग की है। कैसे किया गया फर्जीवाड़ा?

आधार कार्ड: कुछ अधिकारीयों ने हाल ही में अपडेट किए गए आधार कार्ड का उपयोग कर गलत पते दर्ज किए।

किरायानामा: फर्जी किरायानामा प्रस्तुत कर यह दिखाया गया कि वे गरीब परिवारों से हैं।

आय प्रमाण पत्र: आवेदन पत्र जमा करने से पहले जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से कमज़ोर दिखाया

गया।

जांच के लिए उठाए जाने वाले कदम

मनोज जाधव ने मांग की है कि-

१. तालुका स्तरीय चयन समिति को पिछले एक महीने में अपडेट किए गए आधार कार्डों की गहन जांच करनी चाहिए।

२. जिस पते पर आधार कार्ड बना है, उसके अतिरिक्त एक और रेजिडेंस प्रूफ की मांग की जाए।

३. फर्जी किरायानामा जमा करने वाले अधिकारीयों के घरों का निरीक्षण किया जाए कि वे वास्तव में वहां रहते हैं या नहीं।

४. आय प्रमाण पत्र केवल आवेदन जमा करने से पहले की मान्य किया जाए। आरटीई प्रवेश

प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ी

बीड़ जिले की २४ निजी स्कूलों में आरटीई के तहत २,२३५ सीटें उपलब्ध थीं, जिनके लिए ५,७८१ आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से २,१८३ छात्रों को मुफ्त प्रवेश के लिए चुना गया।

पहले इन छात्रों को १४ फरवरी से २८ फरवरी तक प्रवेश लेने का समय दिया गया था, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर १० मार्ग कर दिया गया।

अब तक जिले में १,२४६ छात्रों का प्रवेश निश्चित हो चुका है।

मनोज जाधव ने कहा कि अगर सख्त जांच नहीं की गई तो असली गरीब और जरूरतमंद बच्चों का हक मारा जाएगा, इसलिए फर्जी प्रवेश को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग

के ३,१९० करोड़ रुपये के

ठेकेंद्रों को फिलहाल रोक

दिया गया है। यह ठेकें

सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में

सफाई कार्यों के लिए दिए गए थे।

क्या है मामला?

शिंदे सरकार के

कार्यकाल में तकालीन स्वास्थ्य मंत्री

तानाजी सावंत ने पुणे की एक निजी

कंपनी को अस्पतालों में यांत्रिक सफाई का ठेका दिया था। आरोप है कि इस कंपनी को काम को कोई अनुभव नहीं था, किंतु भी उसे यह ठेका सीधा गया।

३० अगस्त २०२४ को इस कंपनी

को तीन साल के लिए ३,१९० करोड़

रुपये का ठेका दिया गया था, जिसमें

सालाना ६३८ करोड़ रुपये खर्च होने

थे।

अब इस फैसले को मुख्यमंत्री

फडणवीस ने रोक दिया है और मामले

की जांच के अदेश दिए हैं।

शिंदे सरकार में अनियमिताओं पर एक और कार्रवाई

फडणवीस के इस कदम को शिंदे

सरकार के कार्यकाल में हुए कथित

पर भी इसी तरह रोक लगाई जाएगी।

(कीमत लगभग २०,००० रुपये), कमर में पोटली में रखी १.५ ग्राम और नकदी ७०० रुपये समेत कुल २७,७०० रुपये की लूट की।

कैसे हुई वारदात?

प्रत्यक्षतर्थीयों के अनुसार, एक युवक वृद्ध महिला के पैरों से टक्राकर गिरने का नाटक करने लगा और भाग गया। इसी दौरान, दूसरे युवक ने महिला के गले से अंजाम दे रहा है। पुलिस को

लगातार ऐसी घटनाओं की शिकायतें मिल रही हैं, जहां जेबतराश और ठग भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की संपत्ति लूट रहे हैं।

परली में अपराधों का बढ़ता

इस घटना को लेकर नागरिकों में डर का माहौल है। स्थानीय

लोगों ने पुलिस प्रशासन से

कड़ी कार्रवाई की मांग की है,

ताकि इस तरह की वारदातों

पर लगाम लगाई जा सके।

परली में वृद्ध महिला से लूट, भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े वारदात

दुबई और दम्माम (सऊदी अरब) के लिए थॉमसन क्लालिटी अंगूर और गणेश या भगवा क्लालिटी अनार की आवश्यकता है।

एक्सपोर्ट क्लालिटी का माल रखने वाले सप्लायर या किसान संपर्क करें।



Tameer Export: MO: 9270574444

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड़ 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड़, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइ